राम बाली

बनाम

स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

अप्रैल 16,2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, न्यायाधिपतिगण).

आपराधिक अन्वीक्षा :

हत्या - चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में दृष्टि साक्ष्य - के बीच विसंगति - का प्रभाव - मृतक के पेट में भोजन की अनुपस्थिति - का साक्ष्य मूल्य - अभिनिर्धारित :भोजन को पचाने मे लगने वाला समय, भोजन की मात्रा आदि अलग अलग व्यक्तियो में अलग अलग होती है - खाली पेट घटना के समय की शुद्धता के बारे में संदेह करने के लिए एक प्रासंगिक कारक नहीं है-केवल जब दृष्टि संबंधी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत था, तो न्यायालय को उसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

दोषपूर्ण जाँच - प्रभाव - अभिनिर्धारित : दोषपूर्ण जाँच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए - जब प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से स्थापित अभियोजन संस्करण द्वारा की जाती है, तो अभियुक्त को केवल दोषपूर्ण जाँच के कारण बरी नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों और अपीलार्थी-अभियुक्त के बीच मुकदमों के कारण दुश्मनी थी और इसी कारण से अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक की हत्या कर दी थी। विचारण अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्वि की पुष्टि की। इसलिए अपील है।

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से, यह तर्क दिया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से दृष्टि साक्ष्य से भिन्न था; कि मृतक ने दोपहर 2 बजे दोपहर का भोजन किया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम से पता चला कि मृतक का पेट खाली था, जिससे साबित हुआ कि घटना रात 9 बजे के आसपास हुई, न कि शाम 6 बजे के आसपास, जैसा कि आरोप लगाया गया है; यह जांच दोषपूर्ण थी क्योंकि बंदूक को फोरेंसिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था; और यह कि सुनवाई बंद होने के काफी देर बाद फैसला सुनाया गया और इसलिये, उच्च न्यायालय के समक्ष दिये गये तर्को पर ठीक से विचार नहीं किया गया।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1. सुनवाई में क्या हुआ, इसका बयान, न्यायालय के निर्णय में अभिलेख इस प्रकार बताए गए तथ्यों के निर्णायक हैं और कोई भी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा इस तरह के बयान का खंडन नहीं कर सकता है। यदि कोई पक्ष सोचता है कि न्यायालय में घटित घटनाओ को फैसले में गलती से दर्ज किया गया है, तो यह पक्षकार पर निर्भर है, जबकि मामला अभी भी न्यायाधीशों के दिमाग में ताजा है जिन्होंने आवश्यक सुधार करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत तर्क देना खुला नहीं है। [200 - सी-डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक, [1982] 2 एससीसी 463, भावनगर विश्वविद्यालय बनाम. पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड, [2003] 2 एस. सी. सी. 11 और रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी, [2003] 6 एस. सी. सी. 595, - पर भरोसा व्यक्त किया।

2.1 . इस दलील में कोई दम नहीं है कि चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य के विपरीत है। यह महज एक लेखक द्वारा व्यक्त की गई कथित राय पर आधारित है। काल्पनिक प्रश्नो के दिये गये काल्पनिक उत्तर, और पाठयपुस्तक लेखको द्वारा कल्पित तथ्यो पर मात्र काल्पनिक और अमूर्त राय, यदि विश्वसनीय और ठोस है, तो दृष्टि साक्ष्य के मूल्य को कम नहीं किया जा सकता है। भोजन के पचने के लिए सामान्य रूप से लगने वाला समय अन्य चीजो के अलावा भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करेगा। गवाहों द्वारा बताए गए घटना के समय की शुद्धता के बारे में संदेह करने के लिए भोजन की मात्रा, वायुमंडलीय स्थितियों और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को तथ्यात्मक रूप से साबित करने की आवश्यकता थी। केवल तभी जब नेत्र संबंधी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह असंगत हो तो न्यायालय को उसके प्रभाव पर विचार करना होता है। [200 - ई-जी।

पट्टीपति वेंकैया बनाम ए. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 1715 और निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 26, पर भरोसा व्यक्ति किया।

2.2 . एक लेखक का दृष्टिकोण, जो केवल कुछ बुनियादी मान्यताओ पर आधारित एक राय है, किसी तथ्य को साबित करने के लिीये दिये गये साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता है - जो हमेशा विभिन्न तथ्यों पर और किसी विशेष मामले की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार निर्भर करता है। [201 - सी]

एच. डब्ल्यू. वी. कॉक्सः मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी 7 वीं संस्करण, पेज 300-302, संदर्भित किया गया।

3.1 . दोषपूर्ण जाँच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन में सावधानी बरतनी चाहिये। लेकिन केवल दोष के कारण किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करना

सही नहीं होगा; यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है तो ऐसा करना जाँच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा [201 - डी-ई)

करनेल सिंह बनाम एम. पी. राज्य, [1995] 5 एस. सी. सी. 518 और पारस यादव बनाम बिहार राज्य, [1999] 2 एस. सी. सी. 126, पर भरोसा व्यक्त किया ।

3.2 . जब चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्ट चश्मदीद गवाहो की प्रत्यक्ष गवाही अभियोजन वृतांत को पूरी तरह से स्थापित करती है तो जांच अधिकारी की ओर से विफलता या चूक या लापरवाही अभियोजन वृतांत की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है। [202 - बी-सी]

अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह, [2003] एस. सी. सी. 518, पर भरोसा व्यक्त किया।

4. निर्णय में देरी होने और इसके कारण इसे कमजोर बनाने की दलील में कोई दम नहीं है। [202 - एफ-जी]

अनिल राय बनाम बिहार राज्य, [2001] 7 एस. सी. सी. 318, पर भरोसा व्यक्त किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 204/2003

आपराधिक अपील संख्या 3406/1984 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.11.2002 से।

एस. बी. सान्याल, यशबंतो दास, डी. के. सिंह और अभिजीत सेनगुप्ता; अपीलार्थी के लिये।

गर्वेश काबरा और रवि प्रकाश मेहरोत्रा; प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठने आक्षेपित फैसले में विशेष न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा दर्ज की गई सजा को यथावत रखा और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में भादंसं) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया । अभियुक्त-अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, सह-आरोपी राजेन्द्र सिंह को बरी कर दिया गया।

जिन पृष्ठभूमि तथ्यों के कारण अन्वीक्ष चलाई गई, वे इस प्रकार है :

शिकायतकर्ता-राम सिंह (पीडब्लू-1) घटना के समय गांव स्वासा में रह रहा था। दिनांक 20.7.82 को शाम करीब 6 बजे जब वह अपने गांव लौट रहा था, प्यारे सिंह (पीडब्लू-2) सह ग्रामीण भी उसके साथ था। रास्ते में उसका भाई प्रेम सिंह (जिसे इसके बाद 'मृतक' कहा जायेगा) जो छानी गांव में रहता था, उससे मुलाकात हुई। वे बस स्टॉप पर आये और डाक बंगले के सामने चबूतरे पर बैठकर बस का इंतजार करने लगे। तभी हमीरपुर से एक बस आई, अपीलकर्ता-रामबली सिंह (ए-1) और राजेंद्र सिंह (ए-2) निवासी ग्राम छानी बुजुर्ग उस बस से उतर गए।

अभियुक्त रामबली के हाथ में एक डबल बैरल बंदूक और दोषमुक्त राजेन्द्र सिंह के हाथ में सिंगल बैरल बंदूक थी। इसके बाद वे पास की एक पान की दुकान पर गये वहां से वे आकर उनके सामने खडे हो गये और उसके भाई मृतक से बोले, "बेईमानः क्या हम तुम्हे मार दें" उस समय रामबली ने अपनी डबल बैरल बंदूक से गोली चलाई और मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने शोर मचाया और आरोपी गांव के अस्पताल की ओर भाग गए। मुकदमों के कारण शिकायतकर्ता और आरोपी रामबली सिंह के परिवार के सदस्यों के बीच दुश्मनी थी और इसी कारण से आरोपी व्यक्तियों ने मृतक प्रेम सिंह की हत्या कर दी थी। घटना के समय कई ग्रामीण वहां मौजूद थे। घटना रिपोर्ट का मसौदा शिकायतकर्ता के निर्देश पर राम किशन गुप्ता

द्वारा तैयार किया गया था, जिसे एफ. आई. आर. के रूप में दर्ज किया गया था और यह प्रदर्श ए-1 है। एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई।

जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और आरोप तय करने के बाद मामले को सुनवाई के लिए रखा गया । अभियोजन पक्ष के मामले को आगे बढाने के लिये 6 गवाहो को परीक्षित कराया गया। । परीक्षित कराये गये छह गवाहों में से, पीडब्लू । और 2 को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया था। खुद को निर्दोष बताने वाले आरोपी ने किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया। उसने यह दलील दी कि शिकायतकर्ता घटना स्थल पर मौजूद नहीं था जैसा कि कथित तौर पर हुआ था। राम किशन गुप्ता नामक व्यक्ति ने उसे उनके गाँव स्वासा से मोटरसाइकिल पर बुलाया था। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 1 और 2 के वृतांत को जो हुआ था उसके सही प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया और उनके साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि का निर्देश दिया। लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सह-अभियुक्त राजेंद्र को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।

अपील के समर्थन में, अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विस्तृत रूप से विश्लेषण नहीं किया है और अपील का गुप्त रूप से निपटारा किया है। चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से नेत्र साक्ष्य से भिन्न था और इसलिए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य पर भरोसा करके गंभीर त्रुटि की थी। हालांकि आरोपी ने कथित तौर पर बंदूक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। अभिलेख पर साक्ष्य यह स्थापित करता है कि गाँव डकैतो से प्रभावित था, जिसके लिये कथित घटना होने से ठीक पहले पुलिस गश्त कर रही थी। एक सिपाही (पीडब्लू-5) गाँव में गया था, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। पीडब्लू 2 ने कहा था कि

मृतक ने लगभग 2 बजे दोपहर का भोजन किया था, जब डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम किया तो उसने पाया कि पेट खाली था, एचडब्लूवी कॉक्स की पाठयपुस्तक "मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी" के संदर्भ में, यह बतायागया कि भोजन को पूरी तरह से नचने के लिये कम से कम 6 घंटे की आवश्यकता होती है। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य, बचाव पक्ष के वृतांत की संभावना को पुष्ट करता है कि कुछ घटना रात 9 बजे के आसपास हुई थी। हालांकि पुलिस स्टेशन से घटना के कथित घटनास्थल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है लेकिन रात करीब 9:30 बजे बिंवार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह स्वीकार किया गया है कि बस या मोटरसाइकिल से पुलिस स्टेशन पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा। रीगर मोर्टिस के संबंध में पोस्टमॉर्टम में उल्लिखित डॉक्टर का दृष्टिकोण भी घटना के समय को असंभव बनाता है जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसलिए, पीडब्लू 1 और 2 सच्चे गवाह नहीं हो सकते। यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय का निर्णय बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों की पृष्ठभूमि में साक्ष्य का कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। चूंकि प्रशंसा में विकृति है और संबंधित गवाहों के बयान की सच्चाई की जांच के लिये आवश्यक देखभाल और सावधानी की कमी है, इसलिए विचारण अदालत और उच्च न्यायालय दोनों का फैसला कमजोर हो जाता है। हालाँकि कई अन्य लोगों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उनको परीक्षित न कराये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्णय सुनवाई बंद होने के लंबे समय बाद दिया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष की गई दलीलों पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। अनिल राय बनाम बिहार राज्य, [2001] 7 एस. सी. सी. 318 में एक निर्णय का संदर्भ यह तर्क देने के लिये दिया गया था कि निर्णय को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। अपीलार्थी ने विशिष्ट

तर्क दिया था कि संबंधित तिथि पर वह पहचान के उद्देश्य से जेल गया था और उपस्थित नहीं था। इस दलील को साबित करने के लिये तीन गवाहों से पूछताछ की गई कि आरोपी-अपीलार्थी घटना के समय मौजूद नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र होने के तर्क को बिना किसी उचित आधार के गलती से खारिज कर दिया गया है।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णयों का समर्थन किया और आग्रह किया कि सबूतो के उचित परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक जांच की गई है और अब तक नीचे के न्यायालयो द्वारा दर्ज किये गये समवर्ती निष्कर्षो में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जहां तक अभियुक्त के अपराध का संबंध है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य और दृष्टि साक्ष्य के बीच विसंगित के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष भी दलील नहीं दी गई थी। प्रतिवादी के अनुसार निर्णय के विलंबित वितरण से संबंधित याचिका को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष केवल दो बिंदुओ पर आग्रह किया गया था वे इस प्रकार है:

(1) किसी भी गवाह ने घटना को नहीं देखा है और अभियुक्त को दुश्मनी के कारण झूंठा फंसाया गया है।

(2) आरोपी राम बाली सिंह 20.7.1982 को पहचान के लिये जेल गया और वह घटना के समय मौजूद नहीं था।

हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय विशेष रूप से दर्ज करता है कि उसके समक्ष केवल दो बिंदुओं का आग्रह किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुनवाई

में जो हुआ उसके बारे में बयान, न्यायालय के फैसले में रिकॉर्ड इस प्रकार बताए गए तथ्यों के निर्णायक हैं और कोई भी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा इस तरह के बयान का खंडन नहीं कर सकता है। यदि कोई पक्ष यह सोचता है कि न्यायालय में हुई घटनाओं को किसी निर्णय में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह पक्षकार का दायित्व है, जबकि मामला अभी भी उन न्यायाधीशों के दिमाग में ताजा है जिन्होंने आवश्यक सुधार करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष इसके विपरीत तर्क देना खुला नहीं है। (देखे - महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और अन्य [1982] 2 एस. सी. सी. 463, भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पलिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड और अन्य, [2003] 20 एस. सी. सी. 111 और रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी, [2003] 6 एस. सी. सी. 595।

अन्यथा भी, यह दलील कि चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र साक्ष्य के विपरीत है, में भी कोई सार नहीं है। यह केवल एक लेखक द्वारा व्यक्त की गई कथित राय पर आधारित है। काल्पनिक प्रश्नों के दिए गए काल्पनिक उत्तर, और पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा कल्पित तथ्यों पर केवल काल्पनिक और अमूर्त राय, नेत्र साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य को कम नहीं कर सकते हैं यदि यह विश्वसनीय और ठोस है। भोजन के पचने के लिए सामान्य रूप से लगने वाला समय अन्य के अलावा भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करेगा। गवाहों द्वारा बताए गए घटना के समय की शुद्धता के बारे में संदेह करने के लिए भोजन की मात्रा, वायुमंडलीय स्थितियों और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों के बारे में तथ्यात्मक रूप से साबित करने की आवश्यकता थी। केवल तभी जब नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत हो तो न्यायालय को उसके प्रभाव पर विचार करना होता है। इस न्यायालय ने पट्टीपति वेंकैया बनाम. आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 1715 में कहा कि चिकित्सा विज्ञान अभी तक मृत्यु

के सटीक समय का निर्धारण करने के लिए इतना परिपूर्ण नहीं है और न ही इसे कम्प्यूटरीकृत या गणितीय तरीके से निर्धारित किया जा सकता है ताकि अंतिम सैकंड तक सटीक हो सके। चिकित्सीय परीक्षण के समय पाए गए पेट की सामग्री की स्थिति समय निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है। क्योंकि यह अनुमान का विषय होगा, इस सवाल पर विश्वसनीय सबूत के अभाव मे कि वास्तव में मृतक ने अपना अंतिम भोजन कब किया था और उस भोजन में क्या शामिल था। निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 26, में यह संकेत दिया गया था कि पाचन के लिए आवश्यक समय भोजन की प्रकृति पर निर्भर हो सकता है। पाचन क्षमता के अनुसार समय भी अलग अलग होता है। पाचन की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है और यह अलग अलग व्यक्तियो और किसी विशेष समय पर व्यक्ति के स्वास्थ्य और कई अन्य अलग अलग कारको में भिन्न होती है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित अपनी पुस्तक एच. डब्ल्यू. वी. कॉक्स द्वारा भी कारकों का उल्लेख किया गया था। (पृष्ठ 300 से 302 पर सातवाँ संस्करण देखें)। एक लेखक का दृष्टिकोण जो केवल कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है, किसी तथ्य को साबित करने के लिए दिए गए साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकता है-जो हमेशा विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है, और किसी विशेष मामले की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार होता है। एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि याचिका में कोई सार नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि केवल तथ्यों की सराहना से संबंधित उक्त याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी।

जाँच को भी दोषपूर्ण बताया गया था क्योंकि बंदूक को फोरेंसिक जांच के लिये नहीं भेजागया था। दोषपूर्ण जाँच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होगी। लेकिन किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष के कारण

बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जाँच योजनाबद्ध रूप से दोषपूर्ण है। (कर्नेल सिंह बनाम एम. पी. राज्य, [1995] 5 एस. सी. सी. 518 - देखे।)

पारस यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य, [1999] 2 एस. सी. सी. 126 में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि जांच एजेंसी द्वारा चूक या कमी की गई है या लापरवाही के कारण दोषपूर्ण जांच हुई है तो अभियोजन साक्ष्य की ऐसी चूक की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और किस हद तक है,ऐसी चूक से सत्य की खोज का उद्देश्य प्रभावित हुआ। अकेले अधिकारियों के दूषित आचरण से सच्चाई का पता लगाने के लिये अदालतो द्वारा सबूतो के मूल्यांकन के रास्ते में बाधा नहीं आनी चाहिये, अगर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री अन्यथा विश्वसनीय और सत्य है; अन्यथा पक्षपाती या इच्छुक अन्वेषक के कहने पर रची गई शरारत को कायम रखा जायेगा और शिकायतकर्ता पक्ष और इस पक्रिया में बडे पैमाने पर समुदाय को न्याय नहीं दिया जायेगा।

जैसा कि रामबिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य [1998] 4 एस. सी. सी. 517 में देखा गया है, यदि इस तरह की परिकल्पित या लापरवाही जांच को प्राथमिकता दी जाती है, तो त्रुटिपूर्ण जांच द्वारा चूक से लोगों का विश्वास और भरोसा न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी में बल्कि न्याय प्रशासन में भी हिल जायेगा। अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य [2003] 2 एससीसी 518 में इस विचार को फिर से दोहराया गया था। जैसा कि अमर सिंह के मामले (उपरोक्त) में उल्लेख किया गया है कि यह निश्चित रूप से बेहतर होता अगर आग्नेयास्त्रों को तुलना के लिए फोरेंसिक परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता। लेकिन बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट बिना किसी निर्णायकता के केवल एक विशेषज्ञ राय की प्रकृति में होगी। जब चश्मदीद

गवाहो की प्रत्यक्ष गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित, अभियोजन पक्ष के बयान को पूरी तरह से स्थापित करती है, आई. ओ. की विफलता या चूक या लापरवाही अभियोजन पक्ष के वृतांत की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी कयों हुई, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है िक कोई बस उपलब्ध नहीं थी और इसलिये, यह केवल तभी किया जा सकता था जब बस उपलब्ध हो। यह सवाल उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था और इसके अलावा, इसके विपरीत किसी भी सामग्री के अभाव में दिया गया स्पष्टीकरण प्रशंसनीय प्रतीत होता है।

एक और तर्क जिस पर जोर दिया गया वह कथित चश्मदीद गवाहो से पूछताछ न करने से संबंधित था। यह तर्क भी उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया । किसी भी मामले में जांच अधिकारी और गवाहों से यह समझाने के लिये पूछताछ की गई है कि दूसरो से पूछताछ क्यों नहीं की गई और उन दावों को खारिज करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। विचारण कोर्ट ने भी इस पहलू का विश्लेषण किया है और आरोपी के तर्क में कोई सार नहीं पाया है।

कथित अनुपस्थिति से संबंधित तर्क की जांच विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। यह देखा गया कि यह दिखाने के लिये कोई सामग्री पेश नहीं की गई कि जिस समय घटना घटी, आरोपी-अपीलकर्ता पहचान के उद्देश्य से जेल में मौजूद था। हमे अन्यत्र रहने की दलील को खारिज करने में नीचे दी गई अदालतो के निष्कर्षो में कोई खामी नहीं मिली।

हम यह भी पाते हैं कि निर्णय में देरी होने और उसे कमजोर बनाने के तर्क में कोई दम नहीं है। अनिल राय के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने केवल शीघ्र निर्णय देने की वांछनीयता पर जोर दिया है। वास्तव में, उक्त मामले में इस न्यायालय

के समक्ष दिये गये फैसले को फैसले में देरी के आधार पर खारिज नहीं किया गया था और गुणदोष के आधार पर निपटाया गया था। फैसले के पैरा 10 और 45 में इस न्यायालय ने एक पक्ष को विकल्पो का संकेत दिया था, जब किसी स्थिति में निर्णय काफी लंबे समय तक नहीं दिया जाता है। हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता को केवल उस कारण से, मामले के विशिष्ट तथ्यो पर, कोई नुकसान हुआ था।

साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन और तथ्य के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। यह न्यायालय आम तौर पर निष्कर्षो की विश्वसनीयता पर विचार नहीं करता है और हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब असाधारण और विशेष परिस्थितियां मौजूद हो जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ हो। यह उस प्रकृति का मामला नहीं है और साक्ष्य न केवल विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, बल्कि जो निष्कर्षों निकले है वे भी योग्य है और रिकॉर्ड पर मौजूद प्रचुर सामग्री द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित हैं। इसलिए, हम इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं पाते है, जिसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

वी.एस.एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।